सीबीआइ पर सवाल

परत-दर-परत

प्रभात कुमार रॉय

बीआइ को सूचना अधिकार के अंतर्गत लाने की मांग को केंद्रीय हुकूमत ने तसलीम करने से स्पष्ट इंकार कर दिया आइ की संपूर्ण कार्य प्रणाली को कानूनी ारदर्शी बनाने की मांग लंबे समय से की ी है। 1500 करोड़ के बॉफोर्स तोप खरीद में केस के मुख्य मुलजिम ऑटाविया को सीबीआइ ने जिस तरह से भारत से ने का मौका फराहम किया और केंद्रीय क इशारे पर जिस तरह से सीबीआइ निरंतर में डांस करती रही, इसके बाद से तो की कानूनी निष्पक्षता पर से भरोसा उठ कूमत के शिकंजे से निकल कर 2 जी केस में सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देशन में ने बहुत कुछ कर दिखाया। प्रायः न व ताकतवर राजनेताओं पर सेंट्रल ब्यूरो वेस्टिगेशन कानून का शिकंजा कसने में ही सीबीआइ के मूल चरित्र पर सवालिया गते रहे। कुल मिलाकर जो छवि अभी ीआइ की निर्मित हुई, वह एक नाकारा ंसी की है, जो कि संविधान के आर्टिकिल्स नून की धाराओं से संचालित न होकर, ाकाओं के हुक्म पर गुलाम की तरह करती रही। विश्व पटल पर भारत जैसे ठित प्रगतिशील गणतंत्र के लिए यह स्थिति खतरनाक है। किसी ठहरे हुए से ही समाज के लिए जांच एजेंसी सीबीआइ गुलाम चरित्र मुनासिब हो सकता है, किंतु शील गणतांत्रिक राजनीतिक- सामाजिक के लिए ऐसे गुलाम चरित्र को अपराध जेंसी राष्ट्रीय कलंक की तरह कायम है। को पूर्ण कानूनी स्वायत्ता (ऑटोनोमी) ए बिना, उसको गुलाम चरित्र से निजात कदाचित मुमकिन नहीं।

सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआइ गुलाम चरित्र दीर्घ काल से सार्वजनिक मुद्दा बना रहा। भारतीय संविधान के कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की मूलतः प्रांतीय सरकार की है, किंतु जब यवस्था के हालात प्रांतीय सरकार के से बाहर होकर बेकाबू हो जाए, केंद्र को कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल लेने का प्रावधान भारतीय संविधान ने किया है। दिल्ली जैसे प्रांतों में जो संघीय क्षेत्र के तहत आते हैं और जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इन सभी में कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्रीय हुकूमत का है। कानून-व्यवस्था का अहम पहलू रहे अपराधों पर सख्त नियंत्रण करना हुकूमत का उत्तरदायित्व रहा है। किसी भी महत्वपूर्ण जटिल अपराध की जांच पड़ताल में जब प्रांतीय सरकार अपनी पुलिस एजेंसी को अक्षम समझती है, तो केंद्र सरकार से मामले की जांच पड़ताल सीबीआइ से कराने का आग्रह करती है। भारतीय राजनीति के शनैः शनैः अपराधीकरण के पश्चात यह बेहद आवश्यक हो गया है कि सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज हुए अपराधियों के प्रभुत्व से पुलिस-प्रशासन को मुक्त कराया जाए, ताकि सत्तानशीन अपराधियों का मुकम्मल सफाया किया जा सके। ताकतवर जांच एजेंसी सीबीआइ को संवैधानिक और कानूनी स्वायत्ता प्रदान करने के लिए जबरदस्त जनमत का सृजन किया जाए।

क्रिमिनल जस्टिस को चुस्त- दुरुस्त करने की दिशा में यथाशीघ्र सार्थक कदम उठाने की बेहद दरकार है। कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्मित जस्टिस वी एस मलिमथ कमेटी ने कहा कि देश में एक तरफ संगठित माफिया गिरोहों के भयावह अपराधों में इजाफा होता रहा और दूसरी ओर सफेदपोश अपराध भी तीव्र गति से बढ़ते रहे। इन अपराधों को काबू में करने के लिए जस्टिस मलिमथ कमेटी ने अ अनुशंसाएं केंद्रीय हुकूमत के समक्ष पेश एक अनुशंसा सीबीआइ को ऑटिनोमी प्र की भी थी, ताकि सीबीआइ किसी भी दबाव से मुक्त होकर सफेदपोश बड़े रा बड़े ओहदेदार अफसरों और कॉरपोरेट अंजाम दिए जाने वाले घोटालों और स्कै जांच-पड़ताल बेखौफ होकर निष्पक्ष रू सके। जस्टिस मलिमथ कमेटी ने क्रिमिनल को चुस्त- दुरुस्त करने के लिए संगीन अ तेज जांच-पड़ताल और त्वरित न्याय के कदम उठाने की अनुशंसा भी की। केंद्रीय जस्टिस मलिमथ कमेटी की रिकमंडेशंस बस्ते मे डाल दिया। केंद्रीय हुकूमत को और कमेटियों की सिफारिशों पर अम अंजाम देना ही नहीं होता तो आखिर उन का करोड़ों रुपये क्यों खर्च किया जाता है

सफेदपोश अपराधियों की जांच-पड़ लीपापोती चलती रहे और कमजोर अदालत में पेश होते रहे और सफेद अपराधी बाइज्जत बरी होते रहें, अतः सी कमजोर और गुलाम बनाए रखो। बस सामंती चरित्र के कथित जनतांत्रिक राजनेताओं की बनी रही। इससे कहीं कोई पड़ता कि ये सत्तानशीन राजनेता किस प सफेदपोश अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण काले अंग्रेज कतई नहीं चाहते। सीबी राजनेताओं की गुलामी से आजाद करने उनके लिए अपने ही हाथों से फांसी का फं गर्दन में डालना होगा। ताकतवर लोकपाल के गठन का प्रश्न हो अथवा ताकतवर सी सृजन का सवाल हो, केंद्र में सांमती सत्तानशीन राजनेताओं से राष्ट्र को क कदाचित नहीं रखनी चाहिए। अब तो य देश का जनमानस ही करेगा कि राष्ट्र माफिया गिरोहों और सफेदपोश संगीन का किस तरह सफाया किया जाए? जाग समझदारी के साथ अपने गणतांत्रिक मता उपयोग करके भारतीय जनमानस भ्रष्ट अपराधी राजनेताओं का पत्ता साफ कर तभी राष्ट्र की तकदीर संवर सकती है।

मोबाइल:09319

केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआइ का संपूर्ण गुलाम चरित्र लंबे समय से सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना रहा

Reproduced by www.hobbyistonboy.com with author's permission